

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 158

जनसंख्या और देशप्रेम

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण और देशभक्ति को एक समान बताया। उन्होंने कहा, 'जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कई समस्याएं खड़ी करेगा। परंतु जनता का एक धड़ा जागरूक भी है.. उसका परिवार छोटा है

और वह इस तरह देश के प्रति अपना प्रेम जाहिर करता है। हमें उनसे सीखना चाहिए।' प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि देश की भारी-भरकम आबादी ने उसके बुनियादी ढांचे, प्राकृतिक संसाधनों और प्रशासनिक तथा शैक्षणिक क्षमताओं पर दबाव डाला है। परंतु एक तरह से देखा जाए तो जनसंख्या की समस्या आज की नहीं है। आबादी का

बढ़ना जारी रहेगा लेकिन इस समस्या का विस्तार नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग के अनुमान के मुताबिक सन 2007 में देश में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तादाद उच्चतम स्तर पर थी। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 2011 में उच्चतम स्तर पर पहुंची और 25 से कम उम्र की मौजूदा पीढ़ी अब तक की सबसे बड़ी तादाद वाली ऐसी पीढ़ी है। देश के महापंजीयक कार्यालय की नमूना पंजीयन व्यवस्था के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) के आंकड़े भी जन्मदर में धीमेपन की पुष्टि करते हैं। देशव्यापी टीएफआर 2001 के 3.24 से घटकर 2011 में 2.53 हुई और 2021 तक इसके केवल 2.20 रह जाने की उम्मीद है।

भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का बड़ा हिस्सा दीर्घजीविता और बेहतर स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल के कारण 60 से अधिक उम्र के लोगों के कारण होगा। यह वांछित भी है। यह समग्र सुधार तमाम भौगोलिक और सामाजिक विविधता को छिपाए हुए है। देश के कई हिस्सों मसलन दक्षिण भारत के राज्यों, कश्मीर और पश्चिम बंगाल में टीएफआर खासतौर पर कम है। यह यूरोप के स्तर पर या उससे भी कम है। कई अल्पसंख्यक समुदायों मसलन ईसाइयों, बौद्धों, सिखों और जैनों में टीएफआर की दर 2.1 से भी कम है। परंतु उत्तर प्रदेश में यह 3 और बिहार में 3.2 है। अन्य हिंदीभाषीय प्रदेशों में भी जन्मदर काफी बेहतर है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री आबादी में ही रही बढ़ोतरी के

प्रबंधन को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो असली चुनौती विकास की है। जनसंख्या नियंत्रण के कई लाभ हैं। अतीत में परिवार नियंत्रण के तरीकों को अपनाने से जो सबक मिले, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। व्यवहारगत बदलाव तो बाहरी प्रोत्साहन से आता है लेकिन सबसे अहम कारक हैं बढ़ता शहरीकरण, आय सुरक्षा तक पहुंच, कम शिशु एवं बाल मृत्यु दर, बेहतर स्वास्थ्य मानक आदि। महिला सशक्तीकरण जिसमें कामकाजी महिलाएं और महिला शिक्षा का प्रभाव शामिल है, वह भी इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। जन्म दर के मसले को देशभक्ति से जोड़ना इस समस्या से निपटने का सही

तरीका नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच के अंतर को अन्य विकास सूचकांकों के माध्यम से बेहतर ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। जाहिर है इस दिशा में बनने वाली नीति में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। संभव है सरकार दो या कम संतान रखने वालों को कुछ प्रोत्साहन देना चाहे। बहरहाल, फिलहाल राजकोषीय स्थिति ऐसी नहीं है कि ऐसा कोई कदम उठाया जा सके। सरकार के पास अन्य तमाम खर्च भी हैं। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए नया खर्च करना बुद्धिमानी नहीं होगी। सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, शहरीकरण बढ़ाने और महिला सशक्तीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।



अजय मोहंती

बॉन्ड बाजार का फूटता हुआ बुलबुला!

भारतीय बॉन्ड बाजार में बन रहे बुलबुले के बारे में हमें चिंतित होने की जरूरत है। बता रहे हैं आकाश प्रकाश

वैश्विक स्तर पर बॉन्ड बाजारों में कुछ अटपटा हो रहा है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। काफी कुछ अप्रत्याशित घटित हो रहा है। ऐसा कुछ पहले नहीं देखा गया था।

- करीब 15 अरब डॉलर मूल्य के बॉन्ड इस समय दुनिया भर में नकारात्मक प्रतिफल दे रहे हैं।
- अमेरिका से बाहर के 43 फीसदी बॉन्ड नकारात्मक प्रतिफल दे रहे हैं और जर्मनी में समूचा सरकारी बॉन्ड प्रतिफल वक्र नकारात्मक हो चुका है।
- यूरोप में विभिन्न जंक बॉन्ड जारीकर्ताओं को उधार पर रकम लेने के लिए भुगतान किया जा रहा है।
- करीब 10 साल पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग तबाह कर देने वाला सब-प्राइम दौर फिर से वापसी करता हुआ दिख रहा है।
- करीब 75 फीसदी वाणिज्यिक रियल एस्टेट ऋण केवल ब्याज हैं जो कि वर्ष 2006 के बाद का सर्वोच्च स्तर है।
- अमेरिकी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में जंक श्रेणी से ठीक ऊपर वाले बीबीबी रेटिंग का आकार इससे पहले कभी भी इतना बड़ा नहीं था।
- अमेरिका में 30 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड का प्रतिफल अब तक के निचले स्तर पर है और इसी समय जापान, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में नकारात्मक बॉन्ड प्रतिफल की स्थिति है। अधिकांश परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड में प्रतिफल वक्र उलटा हो गया है।
- वर्ष 2008 में जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली पतन के कगार पर थी तब जी-7 देशों के सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल

तीन फीसदी रहा था। आज उन्होंने बॉन्ड का प्रतिफल एक फीसदी से भी नीचे आ चुका है।

- ऑस्ट्रिया के 100 वर्षीय बॉन्ड की कीमतें परवलयाकार बढ़ी हैं। गत 12 महीनों में बॉन्ड का मूल्य 110 से बढ़कर 185 हुआ है और पिछले दो महीनों में ही यह 150 से बढ़कर 185 हो चुका है। बॉन्ड मूल्य की यह सारिणी देखने में दिग्गज तकनीकी कंपनियों के सुनहरे दिनों की तरह लगती है।
- नियत आय बाजार में कीमतों के इस तरह काफी बढ़ा-चढ़ाकर रखने की दो संभावित व्याख्याएं हैं। पहली, नियत आय बाजार वृद्धि एवं मुद्रास्फीति दोनों मौजूद पर एक बेहद कमजोर परिदृश्य की तरफ इशारा कर रहा है। प्रतिफल वक्र का उलटा होना इस तरह संकेत देता है कि एक मंदी आसन्न है और नकारात्मक वास्तविक प्रतिफल बताते हैं कि बाजारों को मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रखने की उम्मीद है। बाजार बेहद कमजोर आर्थिक वृद्धि और अवस्फीति का जोखिम बढ़ने के परिदृश्य को आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा व्यापार युद्ध और वैश्विक स्तर पर कंपनियों के प्रति भरोसा कम होने से हम एक वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ सकते हैं जो कि असंभव नहीं लगता है। लेकिन उस स्थिति में भी बॉन्ड की कीमतें बढ़ी हुईं नजर आती हैं।
- इक्विटी बाजारों में बुलबुलों का होना सामान्य बात है। हम तमाम देशों में समय-समय ऐसा होते हुए देख चुके हैं। इनमें शायद सबसे बड़ा बुलबुला डॉट-कॉम का था जो मार्च 2000 में फूट गया। बॉन्ड बाजारों को कहीं अधिक टिकाऊ माना जाता है। निवेशक एक टिकाऊ एवं सुरक्षित आय के लिए ही बॉन्ड की तरफ रुख करते हैं, न कि कीमतों

में जोरदार उछाल के लिए। आम तौर पर मीडिया भी बॉन्ड बुलबुलों की पहचान पर अधिक ध्यान नहीं देता है। हालांकि हाल में हमें बॉन्ड निवेशकों के बीच बुलबुले जैसा आचरण दिखने लगा है। एक परंपरागत बुलबुले में निवेशकों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वे जो संपत्ति खरीद रहे हैं उसका वास्तविक मूल्य क्या है? वे इसे लेकर आश्चर्य होते हैं कि वे जरूरत पड़ने पर थोड़े समय में ही खरीदी गई संपत्ति को किसी और को बेच देंगे। आज के 15 वर्षीय बॉन्ड को नकारात्मक प्रतिफल देने के बावजूद अगर कोई खरीदता है तो उसका इरादा उसे परिपक्व होने तक बनाए रखने और पूंजी का तयशुदा नुकसान उठाने का कर्ज नहीं होता है। वैसे नकसान उठाने खरीद रहे हैं ताकि किसी और खरीदार को ऊंचे भाव पर बेच सकें।

बुलबुले-जैसे माहौल में निवेशक मौजूदा आर्थिक हालात को भविष्य में भी आरोपित करने लगते हैं। हमारे बॉन्ड बाजार में 30 वर्षों तक तेजी रही है। बाजार में तेजी का यह दौर राजकोषीय मजबूती, उत्पादकता में वृद्धि और भ्रूमंडलीय डॉट-कॉम लाहों का नतीजा था। ब्याज दरों एवं मुद्रास्फीति में 30 वर्षों के भीतर लगातार गिरावट रही है। हालांकि इसकी संभावना काफी कम है कि आगे भी यह रुझान कायम रहने वाला

है। न तो ब्याज दर और न ही मुद्रास्फीति में आगे और कमी की गुंजाइश रह गई है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि भविष्य में वे मुद्रास्फीति को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मुद्रास्फीति के लगातार लक्ष्य से नीचे रहने को ब्याज दरों में आगे और कटौती के लिए आधार बताया जाता रहा है। इसी तरह सरकारें राजकोषीय दायित्व निभाने में चूकती जा रही हैं। अधिक खर्च करने पर सरकारों को मत मिल रहे हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में भी राजकोषीय संयम के अधिक मुरीद नहीं रह गए हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भी अब अवरूद्ध नजर आती है। एक के बाद एक देश में व्यापार एवं आब्रजन संबंधी बाधाएं खड़ी हो रही हैं। भारत और चीन में उदारीकरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के अवस्फीतिकारी आघात दोहराए जाने की संभावना नहीं है। दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र में उत्पादों की कीमतों वैश्विक स्तर पर कम कर पाने की क्षमता नहीं है।

इन कारणों के उलट जाने से क्या हम वास्तव में उम्मीद कर सकते हैं कि बॉन्ड कीमतों से मिल रहे संकेतों के हिसाब से मुद्रास्फीति अब आगे से कम होती रहेगी? बुलबुलों के मामले में मूल्य-निर्धारण बहुत मायने नहीं रखता है। आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। बॉन्ड की कीमतें ऐसे तरीके हो रही हैं जैसे वृद्धि एवं मुद्रास्फीति लौटकर ही नहीं आएंगी। सिद्धांत कहता है कि कर्ज का पहाड़ वैश्विक अर्थव्यवस्था को नीचे की तरफ घसीट रहा है। जितना अधिक कर्ज दिया जाता है, वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के अभाव की स्थिति उतनी ही मजबूत होती जाती है। ऐसे हालात सशक्त होने पर निवेशक उतना ही अधिक कर्ज लेते हैं क्योंकि वृद्धि नदारद रहने पर उन्हें यही परिसंपत्ति समझदार लगती है। यह खुद को सशक्त बनाने की कवायद लगती है।

सामान्य सहज बुद्धि कहती है कि ये प्रतिफल स्तर अवास्तविक हैं। आखिर ग्रीस में उधारी की लागत अमेरिका से कम कैसे रह सकती है? निवेशक ऑस्ट्रिया के 100 वर्ष वाले बॉन्ड के पीछे क्यों भागेंगे जबकि प्रतिफल में एक फीसदी की भी वृद्धि से 30 फीसदी पूंजी का नुकसान हो जाएगा? सभ्य आर्थिक प्रणाली में पैसे की कीमत ही सबसे अहम संकेत है। बाकी सब कुछ जोखिम-मुक्त दर से इतर तय होता है। कुत्रिम रूप से कम जोखिम-मुक्त दर सभी परिसंपत्ति संवर्गों में कीमत संबंधी विकृति पैदा करेगी। वास्तविक दरों के शून्य हो जाने पर भी परिसंपत्ति समूहों में मूल्य की खासी उठापटक देखी जा सकती है। इसके अनचाहे नतीजे होंगे।

अगर भारत विदेशी मुद्रा सांवरिन बॉन्ड जारी करने का फैसला करता है तो उसके लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। यह बॉन्ड जारीकर्ताओं का बाजार है। आप नाममात्र के प्रतिफल पर पैसे जुटा सकते हैं, लिहाजा इसका फायदा उठाइए। अगर एक बाजार या परिसंपत्ति समूह एक बुलबुले जैसे माहौल में हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करना चाहिए। (लेखक अमांसा कैपिटल से संबद्ध हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

सरकारी व्यय में कटौती से कुछ योजनाओं पर लगेगा ताला ?

सरकार के भीतर अब व्यापक स्वीकारोक्ति हो चुकी है कि इसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से राजकोषीय राहत पैकेज लाने या सरकारी व्यय बढ़ाने की गुंजाइश काफी सीमित रह गई है। यह आभास आने वाले हफ्तों में अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए घोषित किए जाने वाले उपायों पर असर भी डालेगा।



दिल्ली डायरी के भट्टाचार्य

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के गैर-अंकेषित अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि इसका सकल कर राजस्व 2018-19 की समान अवधि के मुकाबले केवल 1.3 फीसदी ही बढ़ा है। इस वित्त वर्ष में सकल कर राजस्व में 18 फीसदी की वृद्धि के बजट लक्ष्य को देखते हुए यह वृद्धि काफी कम है। यह तुलना वर्ष 2018-19 में संकलित कर संग्रह के अंतिम आंकड़ों पर आधारित है, न कि बजट में पेश किए गए संशोधित अनुमानों पर। लिहाजा वृद्धि के ये आंकड़े चालू वित्त वर्ष में किए जाने वाले राजस्व प्रयासों का एक अधिक वाजिब तरीका दिखाते हैं।

इस तरह अप्रैल-जून 2019 तिमाही में कॉर्पोरेट कर संग्रह भी महज छह फीसदी बढ़ा। हालांकि व्यक्तित्व आयकर और सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व में वृद्धि क्रमशः 12 फीसदी और 16 फीसदी रही। पहली तिमाही में संकलित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) 28 फीसदी की दर से बढ़ा। लेकिन देश में पेट्रोल एवं डीजल के उपभोग यानी आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार का संकेत देने वाला उत्पाद शुल्क सिंह करीब आठ फीसदी तक गिर गया। यह विरोधाभास हमारे लिए चिंता की वजह है।

ऐसे में आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार ने अपने व्यय पर लगाम लगा दी है। चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में भी सरकार का राजस्व व्यय महज छह फीसदी की दर से ही बढ़ा है। यह वृद्धि दर पूरे साल के राजस्व व्यय के लिए अनुमानित 22 फीसदी वृद्धि की तुलना में काफी कम है।

पूंजीगत व्यय की नकेल तो और अधिक कस दी गई है। इसके वर्ष 2019-20 के पूरे साल में करीब 11 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन अप्रैल-जून की अवधि में पूंजीगत व्यय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही की तुलना में हुए खर्च से 27 फीसदी तक नीचे आ चुका है।

वित्त मंत्रालय के पास यह तय करने के लिए केवल छह महीने ही रह गए हैं कि केंद्र सरकार की बाकी सभी परियोजनाओं एवं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर उनके निष्प्रभावी या फालतू हो जाने का फैसला किया जाए।

अगर वित्त मंत्रालय के मुख्यालय नार्थ ब्लॉक का मिजाज ऐसा ही बना रहा तो सरकार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित सभी तरह की योजनाओं एवं परियोजनाओं पर अब करीबी नजर रखेगी। सार्वजनिक वित्त-पोषित योजनाओं एवं परियोजनाओं को संजोरी एवं उनकी समीक्षा के संबंध में जारी एक पुराने परिपत्र को कुछ हफ्ते पहले ही व्यय विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है।

इस अधिसूचना के दो निर्देश खास अहमियत वाले हैं क्योंकि वे किसी खास संदर्भ में उसके निहित मंतव्य को दर्शाते हैं। पहला, यह सभी केंद्रीय मंत्रालयों को व्यय विभाग की सैद्धांतिक पूर्वानुमति नहीं मिलने से संजोरी नहीं होनी चाहिए या परिचय पत्र पर कोई भी नई योजना या परिचय पत्र शुरू करने से रोकता है। इस तरह यह निर्देश किसी भी मंत्री या सचिव को अपने क्षेत्राधिकार में कोई भी नई योजना शुरू करने से रोकता है जिससे नया खर्च बढ़ने वाला हो। इसी के साथ वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों को अब बेअसर

एवं व्यर्थ हो चुकी योजनाओं एवं परियोजनाओं के विलय या पुनर्गठन या उन्हें बंद किए जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को भी कहा है। यहाँ पर इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि एक नई योजना शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी लेनी होगी, वहाँ किसी फालतू योजना को बंद करने या उसके पुनर्गठन की शुरुआत किसी भी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नार्थ ब्लॉक की पूरक-अनुमति के बगैर ही की जा सकती है।

दूसरे निर्देश के कई योजनाओं के भविष्य के लिए अहम निहितार्थ हैं। वर्ष 2016 में केंद्रीय क्षेत्र द्वारा संचालित कुल योजनाएं 300 थीं लेकिन उन्हें सरल एवं कारगर बनाने की कवायद पिछले तीन वर्षों से चल रही है। इसी तरह केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं उसकी भागीदारी वाली योजनाओं की संख्या घटाकर केवल 30 पर लाई गई थी। ऐसी योजनाओं के भविष्य पर फैसला करने की पहली समयसीमा मार्च 2017 थी जब बारहवीं पंचवर्षीय योजना का भी समापन हो रहा था। ऐसी समीक्षा की दूसरी एवं अंतिम समयसीमा मार्च 2020 होने वाली है। उसी समय 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के लागू होने की मियाद भी पूरी होगी।

वित्त मंत्रालय के पास यह तय करने के लिए केवल छह महीने ही रह गए हैं कि केंद्र सरकार की बाकी सभी परियोजनाओं एवं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर उनके निष्प्रभावी या फालतू हो जाने का फैसला किया जाए। दूसरा निर्देश दिखाता है कि मार्च 2020 के बाद भी जारी रखने लायक ऐसी सभी योजनाओं पर समयावधि समीक्षा का प्रावधान लागू होगा। इसके पीछे दलील यह है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी और केवल वह योजनाएं इस समयवधि समीक्षा से बच सकती हैं जिन्हें फंड उपलब्धता के आधार पर आगे भी जारी रखने को सही ठहराया जा सके।

इस लिहाज से अगले छह महीने ही यह तय करेंगे कि कौन सी केंद्रीय योजना समेट ली जाएगी और किस योजना का अब नजर आने शुरू होगा। ऐसी स्थिति में आने वाले महीनों में हमें इन योजनाओं के पक्ष एवं विपक्ष में गोलबंदी भी तेज होती हुई नजर आएगी।

कानाफूसी

‘मेरा गौरव दीदी’

तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में जो भी नुकसान हुआ उसे दूर करने के लिए पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ पुराने जुड़ाव तक का सहारा ले रही है ताकि उसे प्रगतिशील समझा जाए। युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है। हम जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक विज्ञापन बिना व्यंग्य के पूरा नहीं होता है और 'मेरा गौरव ममता' नामक यह विज्ञापन भी अपवाद नहीं है। पिछले दिनों आयकर विभाग ने विभिन्न पूजा समितियों को आय कर रिटर्न दाखिल करने को कहा था। इस विषय पर केंद्र सरकार की चुटकी लेते हुए बने एक विज्ञापन में दिखाया गया है कि एक कर अधिकारी देवी दुर्गा से रिटर्न फाइल करने को कहता है। विज्ञापन के अंत में एक संदेश उभरता है जो कहता है कि क्या अब देवी को भी अपना पैन नंबर और आधार कार्ड देना होगा ?

‘गंभीर’ हो रहे गंभीर

खबरों के मुताबिक क्रिकेट के खेल से राजनीति के मैदान में पदार्पण कर चुके भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने एक डिजिटल एजेंसी की सेवाएं ली हैं जो ऑनलाइन रूप से उनके राजनीतिक कद का ख्याल रखेगी। डिजिटल स्तर पर उनकी पहचान मजबूत करने के अलावा एजेंसी अगले वर्ष होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में उनकी रणनीति तैयार करने का काम भी करेगी। हालांकि अभी जल्दी है लेकिन पार्टी के कई सदस्यों का कहना है कि पूर्वी दिल्ली के सांसद के रूप में चुनाव के पहले पार्टी की ओर से संभावित मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए। यह एजेंसी पहले सिनेमा और खेल जगत के लोगों के साथ काम कर चुकी है लेकिन राजनीति में उसे यह पहला बड़ा काम मिला है।



आपका पक्ष

समान कार्य और समान वेतन लागू हो

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभागों में कार्य करने के लिए विभिन्न शासकीय पदों पर सविदा, दैनिक वेतन भोगी के रूप में अनुबंधित कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। ऐसे पद अस्थायी होते हैं जो एक निश्चित समय तक के लिए होते हैं। इसके बाद सरकार या तो कर्मचारियों को हटा देती है या प्रतिवर्ष इनके करार को बढ़ाते रहती है। ऐसे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इनके वेतन भी स्थायी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम होते हैं। विभागों में कार्य करने वाले नियमित कर्मचारी भी इनसे अत्यधिक कार्य लेते हैं और वे भविष्य में नियमित होने की आस में निरंतर बेहतर कार्य करते रहते हैं। इन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की मानसिकता यही होती है कि उनके द्वारा किए गए बेहतर कार्य और अधिकारियों की प्रशंसा के लाभ से वे एक दिन नियमित हो जाएंगे। ऐसे अस्थायी



और अनुबंधित नियुक्ति से कर्मचारियों का सिर्फ शोषण ही होता है। शासन द्वारा कम वेतन देना, सुविधाओं से वंचित रखना, नौकरी में अस्थिरता बने रहना आदि इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और समस्या बनी रहती है। स्थायी कर्मचारियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा इनसे कार्य लेना इनका स्थायी होने की संभावना तलाशना इनकी

सरकार को अनुबंध के आधार पर नियुक्तियों को बाद में स्थायी करना चाहिए

समस्या के मुख्य कारणों में से एक है। उच्चतम न्यायालय ने भी 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर मुहर लगाते हुए कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी स्थायी

की तरह मेहनताना पाने के हकदार हैं। फिर भी सरकार इस ओर कदम नहीं उठा रही है और न ही किसी प्रकार की दिलचस्पी दिखा रही है। लिहाजा वर्तमान समय की जरूरत है कि पदों पर भर्ती स्थायी लिया जाए। अगर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जा रही है तो उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह समान वेतन और सुविधाएं दी जाएं। इससे न सिर्फ वह आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि सरकारी महकमे में कार्य करने के लिए लोगों को एक अनुकूल माहौल मिलेगा।

अमित पांडेय, बिलासपुर

पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प दोहराए हैं अगर उन पर संजीदगी से अमल हो तो अर्थव्यवस्था को लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में पांच खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य बड़ा है पर सब साथ मिलकर प्रयास करें तो हासिल करना कठिन नहीं है। अर्थव्यवस्था की मजबूती सभी क्षेत्रों के सम्मिलित सहयोग से आती है। उसमें कोई भी क्षेत्र कमजोर रह जाता है तो वह विकास दर को ऊपर नहीं बढ़ने देता। इसलिए केंद्र सरकार ने सभी विभागों व सभी राज्य सरकारों को इसमें सहभागी बनाने की कोशिश की है। इससे बेहतर नतीजों की उम्मीद बनती है। जीएसटी जैसे फैसलों के नतीजे अब नजर आने शुरू हुए। कौशल विकास व मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के परिणाम भी अब दिख सकते हैं। लेकिन इनके लिए औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ अंदरूनी और बाहरी बाजार के आकार में विस्तार पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा।

अजीत कुमार गौतम, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।